

अंचल कार्यालय, बोआरीजोर ।

आदेश

अतिक्रमण वाद सं०-०१/२०२०-२१

पटवारी मुर्मू ग्राम प्रधान मौजा-कुशबिल्ला बनाम् रौशन अंसारी पे०-शुकर अली
अंसारी वगैरह ग्राम-कुशबिल्ला

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अनुपाल

23⁰⁷/₂₅

इस वाद का प्रारंभ आवेदक पटवारी मुर्मू ग्राम-प्रधान मौजा-कुशबिल्ला थाना नं०-२० पंचायत-कुशबिल्ला थाना-राजाभीठा अंचल-बोआरीजोर जिला-गोड्डा के आवेदन से होता है, जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम-कुशबिल्ला पंचायत-कुशबिल्ला थाना-राजाभीठा के कुछ व्यक्तियों द्वारा गाँव के गौचर जमीन पर मकान बनाकर एवं ईट का भट्टा लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच कराई गई। जाँचोपरांत उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-कुशबिल्ला थाना नं०-२० के गैरमजरूआ खाता सं०-६२ के दाग सं०-७९१ किस्म गौचर के अंतर्गत कुल-१३ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर मकान, झोपड़ी आदि बनाया गया है। साथ ही अतिक्रमणकारियों की सूची भी संलग्न की है, जो संलग्न है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त भूमि सरकारी भूमि है जो गैरमजरूआ पंजी में किस्म गौचर कहकर दर्ज है जो बिहार/झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, १९५६ के प्रावधानों के अंतर्गत एक लोक भूमि है पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है जिसके आधार पर:-

१. उक्त मौजा के चिन्हित अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने हेतु झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम २००० की धारा-३ के अंतर्गत फॉर्म-I में नोटिश निर्गत किया गया जिसके आलोक में अतिक्रमणकारियों द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि उक्त भूमि पर उसके दावा व हक /अधिकार बनता हो।
२. अतिक्रमित भूमि न तो अतिक्रमणकारियों की कृषि भूमि से जुड़ी है और न ही कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में है। अतः उक्त भूमि बंदोवस्ती हेतु प्रतिबंधित है। बिहार/झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम १९५६ की धारा ६(१) के तहत अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध दंड का प्रावधान है।
३. अतः बिहार/झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम २००० की धारा ६(१) (C) के अंतर्गत उक्त लोक भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित करता हूँ।
४. लोक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के जारी होने के १५ दिनों के अंदर अतिक्रमण हटा लें।
५. यदि निर्दिष्ट समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो अतिक्रमित भूमि पर विद्यमान सभी प्रकार की संरचनाएँ जब्त कर ली जाएगी और आवश्यकतानुसार बल का प्रयोग करके उन्हें हटा दिया जाएगा।
६. राजस्व उपनिरीक्षक बिहार/झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम १९५६ एवं दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के प्रावधानों के तहत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर सूचित करें।

कार्यवाहक सहायक, अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध फॉर्म-II में नोटिस निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
बोआरीजोर।